@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'सर्वधर्म समभाव व समाज का ताना-बाना और मजबूत होगा'

वर्ष-14, अंक-22 16-30 नवम्बर, 2019 (पाक्षिक) ₹20

अयोध्या पर निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या की पूरी 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार रामलला विराजमान को सौंप दिया जाये।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सैकड़ों वर्ष पुराने इस विवाद पर 40 दिनों की रोजाना सुनवाई के बाद एकमत से रामजन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया।

पीठ ने कहा कि विवादित स्थल में ही भगवान राम का जन्म होने के बारे में हिन्दुओं की आस्था अविवादित है। सीता रसोई, राम चबूतरा और भण्डार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक तथ्य के गवाह हैं।

संविधान पीठ ने यह माना कि विवादित स्थल के बाहरी बरामदे में हिन्दुओं द्वारा व्यापक रूप से पूजा अर्चना की जाती रही है।

संविधान पीठ ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे मिली संरचना इस्लामिक नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया कि नयी मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए।

'सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है'

राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाकर रवाना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 'शहरी भूकंप खोज एवं बचाव, 2019' पर शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली स्थित पटेल चौक पर सरदार बल्लभभाई पटेल जयंती (31 अक्टूबर) पर उन्हें श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

पटना (बिहार) में स्व. कैलाशपति मिश्र की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में 'आयुष्मान भारत योजना' के लाभार्थियों से संवाद करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोनः +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्सः +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **'विवादित स्थल में ही भगवान राम का जन्म और वे ही भूमि के स्वामी'**

सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नयी मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर...

वैचारिकी
यह मेरा नहीं सबका है और इसलिए राष्ट्र का है 20

श्रद्धांजलि
कैलाशपति मिश्र एवं कमल शर्मा की स्मृति को नमन 22

लेख
राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनाराः आरसेप में भारत को कमजोर करने के बीज कांग्रेस सरकार ने बोए थे 24

साक्षात्कार
ईमानदार व पारदर्शी भाजपा सरकार के चलते हरियाणा में हमें पुनः जनसमर्थन मिलाः अनिल जैन 26

अन्य
आइए एक नई शुरुआत करते हैंः नरेन्द्र मोदी 11
जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हुआ 17
4.58 लाख अधूरे फ्लैटों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी 19
'हमें अपनी विविधता में एकता पर गर्व है' 28
भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर 29
भारत-जर्मनी के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा समेत 17 क्षेत्रों में समझौता 30
सशक्त आसियान से भारत को काफी लाभ मिलेगाः नरेन्द्र मोदी 32
'गुरुनानकदेव जी का प्रभाव भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में है' 34

14 **दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ**

दीपावली के दिन 27 अक्टूबर को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता...

16 **राज्य में शानदार काम कर रही है राजग सरकारः जेपी नड्डा**

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार की राजग के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार शानदार काम...

18 **करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पित**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर को गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे और यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यात्री टर्मिनल को एकीकृत जांच चौकी...

23 **कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल के योगदान को हमेशा याद रखेगाः अमित शाह**

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई ...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

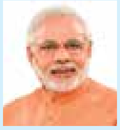

जो हमसे युद्ध में नहीं जीत सकते, वो हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं, इसे तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सदियों की ऐसी ही कोशिशों के बावजूद हमें कोई मिटा नहीं सका, हमारी एकता को परास्त नहीं कर सका। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

@AmitShah

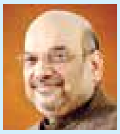

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीडीसी चुनाव में 98% मतदान इस क्षेत्र की जनता का लोकतंत्र में अटूट विश्वास का परिचायक है। 370 और 35A यहां के विकास में सबसे बड़ी बाधा थे। अब यह जन प्रतिनिधि गांव-गांव तक विकास को ले जाने का काम करेंगे। मैं इन सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देता हूं।

@JPNadda

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में 'आयुष्मान भारत योजना' के लाभार्थियों से मिलकर उनसे चर्चा की। इस योजना का प्रत्येक लाभार्थी आज मोदीजी को आशीर्वाद दे रहा है। इस जीवनदायी योजना के तहत देश की 50 करोड़ से अधिक जनता बीमार होने पर अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकती है।

facebook

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए लगभग 11 माह हो गए हैं। एक बार भी रिक्त शासकीय पद भरने का विज्ञापन नहीं निकाला गया। बच्चे अधिकतम आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं। रोज़गार देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से मेरा सवाल है कि रिक्त पद आखिर कब तक भरे जाएंगे?

— **शिवराज सिंह चौहान**

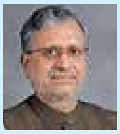

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में कालेधन के खिलाफ एसआईटी का गठन किया और पहले कार्यकाल में आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया था। भ्रष्टाचार, कालाधन और टेरर फंडिंग के विरुद्ध जो चौतरफा अभियान शुरू किया गया, उसी के तहत नोटबंदी का साहसिक निर्णय भी किया गया था। जिस कांग्रेसनीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसआईटी का गठन नहीं किया, वही नोटबंदी का विरोध कर कालाधन रखने वालों का बचाव भी करती रही। नोटबंदी के बाद कई चुनावों में जनता ने इस फैसले के समर्थन में मतदान किया।

— **सुशील कुमार मोदी**

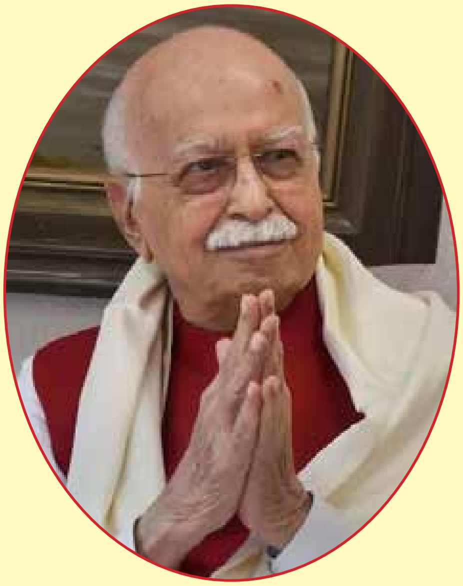

जीवेम शरदः शतम्!

जन्म : 08 नवम्बर

कमल संदेश परिवार की ओर से
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं
भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री
श्री लालकृष्ण आडवाणी को
उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनायें!

सर्वोच्च न्यायालय का श्रीरामजन्मभूमि पर ऐतिहासिक निर्णय

श्रीरामजन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के बहुप्रतीक्षित निर्णय का पूरे देश में स्वागत हुआ है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को पूरे दायित्वबोध एवं एकजुटता के साथ आदरपूर्वक स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस सर्वसम्मत निर्णय को देश के विभिन्न समुदायों ने सर्वसम्मति के साथ सम्मान दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र, इसके संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया की शक्ति ही है कि जो विषय अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता था, उसका भी समाधान कानून एवं न्याय के अंतर्गत संभव हुआ है। श्रीरामजन्मभूमि का विषय सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से देश में चला आ रहा था तथा दशकों से विभिन्न न्यायालयों से होता हुआ जिस प्रकार के परिणाम को प्राप्त हुआ, उससे निश्चय ही इतिहास के पन्नों में इस निर्णय का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना सुनिश्चित है। इस जटिल प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए संविधान पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने जिस प्रतिबद्धता, तत्परता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिखाया है, यह अभिनंदनीय है। संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय ने न्यायपालिका एवं न्यायिक प्रक्रिया की प्रतिष्ठा को कई गुणा बढ़ा दिया है और साथ ही पूरे विश्व को भारतीय संविधान की शक्ति से एक बार पुनः परिचय कराया है। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण की यात्रा लंबी एवं संघर्षपूर्ण रही है। श्री रामजन्मभूमि विषय पर देश में व्यापक बहस हुई है तथा इसने सामाजिक, न्यायिक, ऐतिहासिक, धार्मिक मान्यताओं एवं आस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपनी छाप छोड़ी है। इससे हमारे संविधान, न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया, राजनैतिक वातावरण एवं लोकतांत्रिक मूल्य और भी सुदृढ़ होकर उभरे हैं। यह किसी समुदाय विशेष की जीत या हार से संबंधित न होकर एक व्यापक संदर्भ में चले बहुस्तरीय प्रक्रियाओं की परिणति है। इसी भावना के साथ पूरे देश ने खुले मन से उदारतापूर्वक इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत किया हैं तथा किसी एक समुदाय विशेष की मानसिकता से ऊपर उठकर पूरे देश ने सौहार्दपूर्वक इसे स्वीकारा है। भारत सदियों से परस्पर सौहार्द, सह–अस्तित्व, सहिष्णुता, सहनशीलता एवं शांति के लिए जाना जाता रहा है। हर परिस्थिति में इन मूल्यों को सर्वोपरि मानकर भारत ने एक लंबी यात्रा पूरी की है। किसी विषय पर विभिन्न मत होते हुए भी निर्णय आने पर संपूर्ण राष्ट्र सहजता से उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता रहा है। युगों–युगों से यही भारत की थाती रही है। आने वाले समय में भी इन्हीं मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर सद्भाव एवं सौहार्द और अधिक सुदृढ़ हो सकता है।

> भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर निश्चित ही भारत के प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की भव्यता को दर्शाएगा और चूंकि एक भव्य मंदिर एक महान राष्ट्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसलिए हर भारतीय को मां भारती के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा ताकि महान राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का जन–जन वाहक बन सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि यह निर्णय न किसी की हार है और न ही जीत। साथ ही उन्होंने आह्वान भी किया है कि समय आ गया है कि राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया जाए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा है कि इस निर्णय से भारत की एकता, अखंडता एवं महान संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होगी। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इन्हीं भावनाओं को परिलक्षित करते हुए कहा है कि भारत अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ एकता के इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए और अधिक सुदृढ़ होता जाएगा। भाजपा ने संतुष्टि के भाव से इस निर्णय का स्वागत किया है तथा कहा है कि इस लंबी यात्रा में सकारात्मकता एवं गंभीरता के साथ इसने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए तथा इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण की राह के सभी बाधाओं को दूर कर दिया है, एक लंबी यात्रा पूर्ण हुई है तथा एक 'नए भारत' के निर्माण के सभी द्वार खुल चुके हैं। भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर निश्चित ही भारत के प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की भव्यता को दर्शाएगा और चूंकि एक भव्य मंदिर एक महान राष्ट्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसलिए हर भारतीय को मां भारती के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा ताकि महान राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का जन–जन वाहक बन सके। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

अयोध्या के रामजन्मभूमि मामले में सर

'विवादित स्थल में ही भगवान राम

सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नयी मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही 134 साल से भी अधिक पुराने इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति सर्वश्री एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल थे।

संविधान पीठ ने अपने 1045 पन्नों के फैसले में कहा कि नयी मस्जिद का निर्माण 'प्रमुख स्थल' पर किया जाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर मंदिर निर्माण के लिये तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला विराजमान को सौंप दिया जाये, जो इस मामले में एक वादकारी हैं। हालांकि यह भूमि केन्द्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में ही रहेगी।

न्यायालय ने कहा कि हिन्दू यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित ढांचे के बाहरी बरामदे पर उनका कब्जा था और उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड अध्योध्या विवाद में अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

संविधान पीठ ने यह माना कि विवादित स्थल के बाहरी बरामदे में हिन्दुओं द्वारा व्यापक रूप से पूजा अर्चना की जाती रही है। संविधान पीठ ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे मिली संरचना इस्लामिक नहीं थी।

न्यायालय ने कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण के साक्ष्यों को महज राय बताना इस संस्था के साथ अन्याय होगा। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवादित स्थल को ही भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम भी इस स्थान के बारे में यही कहते हैं।

पीठ ने कहा कि विवादित ढांचे में ही भगवान राम का जन्म होने के बारे में हिन्दुओं की आस्था अविवादित है। यही नहीं, सीता रसोई, राम चबूतरा और भण्डार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक तथ्य

र्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

का जन्म और वे ही भूमि के स्वामी'

रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश

एस. ए. बोबडे

धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़

अशोक भूषण

एस. अब्दुल नजीर

की गवाह हैं।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक स्थापित नहीं किया जा सकता और ये विवाद का निबटारा करने में सूचक हो सकते हैं।

संविधान पीठ ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान- के बीच बराबर बराबर बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी।

रामलला विराजमान की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा, 'यह बहुत ही संतुलित है और यह जनता की जीत है।" इस वाद के एक अन्य पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि उसे उसका दावा खारिज होने का कोई अफसोस नहीं है। ■

फैसले को जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिएः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसले पर शांति एवं सद्भाव बनाये रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत किया है। शांति एवं सद्भाव कायम रहे।

श्री मोदी ने कहा कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उल्लेखनीय है, क्योंकि यह इस बात को उजागर करता है कि किसी भी विवाद को कानून की उचित प्रक्रिया के जरिये हल किया जा सकता है। यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और दूरदर्शिता की पुष्टि करता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले ने दशकों से चल रहे विवाद को एक अंजाम तक पहुंचाया है। सुनवाई के दौरान हरेक पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में लोगों के विश्वास को और बढ़ाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि आज के फैसले के दौरान 130 करोड़ भारतीयों ने शांति एवं सद्भाव बनाए रखा जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकता और एकजुटता की यह भावना हमारे राष्ट्र को विकास के लिए शक्ति प्रदान करे। हरेक भारतीय सशक्त बने।

'सर्वधर्म समभाव' व समाज का ताना-बाना और मजबूत होगाः अमित शाह

श्रीराम जन्मभूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 नवंबर को कहा कि मैं श्रीराम जन्मभूमि मामले पर सर्वसम्मति से दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक और सर्वसमावेशी निर्णय का ह्रदय से स्वागत करता हूं। इससे सर्वधर्म समभाव व समाज का ताना-बाना और मजबूत होगा। इस निर्णय से न केवल वर्षों से चले आ रहे इससे जुड़े सभी मुद्दों का समाधान हुआ है, बल्कि यह निर्णय देश की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल भी देने वाला है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सभी समुदायों और सभी धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति और सौहार्द से परिपूर्ण 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहें। भारतीय जनता पार्टी विश्वास व्यक्त करती है कि इस निर्णय से इस मामले से जुड़ी सभी चिंताएं समाप्त होंगी और भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ एकता के सूत्र पर और मजबूत होकर चलेगा।

श्री शाह ने कहा कि दशकों से चले आ रहे श्रीराम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली व सभी न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूं। श्रीराम जन्मभूमि कानूनी विवाद के लिए प्रयासरत सभी संस्थाएं, पूरे देश के संत समाज और अनगिनत अज्ञात लोगों जिन्होंने इतने वर्षों तक इसके प्रयास किया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए स्वागत योग्य एवं सराहनीय कदम उठाये हैं। अदालत के इस निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाए कि संपूर्ण भारत एकजुट है एवं भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत की महान सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के साथ देश शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, यही हमारी कामना है।

यह निर्णय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी समावेशी विचारों का एक उदाहरण: जेपी नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 'श्री राम जन्मभूमि' मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक और सर्वसम्मत निर्णय का स्वागत किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि "यह निर्णय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी समावेशी विचारों का एक उम्दा उदाहरण है। हम इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले ने न केवल इससे संबंधित सभी मुद्दों को हल किया है, बल्कि यह देश की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और मजबूती देने वाला है।

भाजपा इस निर्णायक और समयबद्ध फैसले के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीशों और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ का आभार व्यक्त करती है, जिसके कारण दशकों से लंबित यह मामला अपने अंजाम तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी देश के उन लोगों का स्वागत और सत्कार करती है जिन्होंने एकजुट होकर देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने-बाने को अक्षुण्ण रखा है।

भारतीय जनता पार्टी देशवासियों से अपील करती है कि वे इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करें और अफवाहों पर ध्यान दिए बिना समानता, सामाजिक सद्भाव और शांति की अमूल्य विरासत को बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम एकजुट हैं और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जैसा कहा कि देश की न्यायपालिका की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए, समाज के सभी पक्षों, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने इस मामले से संबंधित सभी पक्षों ने इसका स्वागत किया है और एक शांतिपूर्ण बनाने के लिए अतीत में भी सराहनीय कदम उठाए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी हम सभी को मिलकर सद्भाव बनाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का स्वागत करती है और विश्वास रखती है कि न्यायालय के निर्णय के बाद इस मामले से संबंधित सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे और भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ 'एकता के सिद्धांतों' पर और मजबूत होगा।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रही है। पालमपुर संकल्प से लेकर आज तक, भाजपा ने इस मुद्दे पर हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान राम मंदिर मुद्दे का हल निकला है। जब भी देश का इतिहास फिर से लिखा जाएगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

'हिंदुओं की आस्था अयोध्या के बारे में भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।'

'खुदाई में मिले अवशेष इस्लामी नहीं थे।'

'यह स्थापित नहीं कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई, पर यह स्पष्ट कि मस्जिद खाली जगह में नहीं बनाई गई'

'ये साबित है कि मुस्लिम आंतरिक अहाते में नमाज अदा करते थे जबकि हिन्दू बाहरी अहाते में पूजा करते थे।'

'मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि 16वीं शताब्दी में मस्जिद के निर्माण से 1857 तक भीतरी अहाते में उनका कब्जा था।'

'हिंदू पक्ष ने यह साबित किया कि मस्जिद वाले स्थान पर ही राम का जन्मस्थान है और 1857 तक राम चबूतरा और सीता रसोई पर उनका कब्जा था।'

हम सभी को मिलकर भव्य राममंदिर का निर्माण करना है: मोहन भागवत

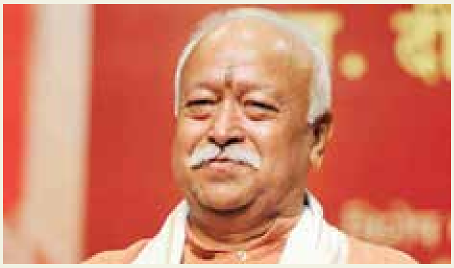

अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 9 नवंबर को कहा कि दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधिसम्मत और 'अंतिम निर्णय' हुआ है और अब अतीत की बातों को भुलाकर सभी को मिलकर भव्य राममंदिर का निर्माण करना है।

श्री भागवत ने कहा, ''रामजन्मभूमि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था और श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का संघ स्वागत करता है। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधिसम्मत अंतिम निर्णय हुआ है।" उन्होंने देशवासियों से संयम बनाये रखने की अपील करते हुए कहा, "इस निर्णय को जय, पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये।"

संघ प्रमुख ने कहा, ''संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को अभिव्यक्त करें।" श्री भागवत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस विवाद के समापन की दिशा में न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्र होगी।

उन्होंने कहा, ''अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी मिलकर रामजन्मभूमि पर भव्य राममंदिर के निर्माण में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।"

पूरी हुई मनोकामना, खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं: लालकृष्ण आडवाणी

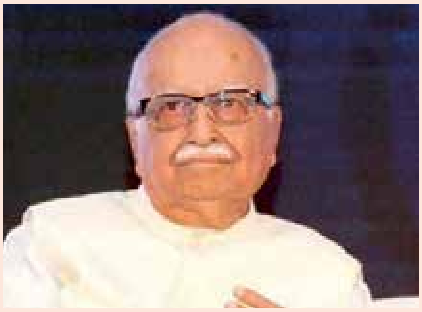

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि वह पूरे दिल से अयोध्या मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के आए फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके रुख की पुष्टि हुई है और वह खुद को धन्य महसूस करते हैं।

इस पल को मनोकामना पूर्ण होने वाला बताते हुए 92 वर्षीय श्री आडवाणी ने कहा कि यह क्षण मेरी कामना पूर्ण होने का है। ईश्वर ने मुझे विशाल आंदोलन में योगदान देने का अवसर दिया।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से अयोध्या में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवाद का पटाक्षेप हो गया और समय आ गया है कि विवाद एवं कटुता को पीछे छोड़कर सांप्रदायिक एकता और सहमति को गले लगाया जाए।

मंदिर आंदोलन को स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आंदोलन करार देते हुए कहा कि इसका लक्ष्य प्राप्त करना फैसले से संभव हुआ है।

उन्होंने फैसले का दिल से स्वागत करते हुए कहा, 'मैं अपने रुख पर कायम हूं और खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एकमत से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया।'

श्री आडवाणी ने जोर देकर कहा कि राम और रामायण भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विरासत में उच्च स्थान रखते हैं। राम जन्मभूमि का करोड़ों देशवासियों के दिलों में पवित्र स्थान है।

श्री आडवाणी ने भारत के विभिन्न समुदायों से अपील की कि वे एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम करें।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पांच एकड़ जमीन अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए देने के फैसले का भी स्वागत किया।

उन्होंने कहा, 'अयोध्या के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का खुले दिल से स्वागत करने के लिए मैं देशवासियों के साथ खड़ा हूं।'

उल्लेखनीय है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते पार्टी ने 1989 के पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था।

श्री आडवाणी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के लिए जनसमर्थन जुटाने हेतु गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू की थी।

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

आइए एक नई शुरुआत करते हैं: नरेन्द्र मोदी

श्रीराम जन्मभूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का पूरा पाठ:

मेरे प्यारे देशवासियो,

मैं दिन भर पंजाब में था और दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा मन कर रहा था कि आपसे भी कुछ संवाद करूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज़ सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है।

साथियो, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया ने ये भी जान लिया है की भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मज़बूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

भाइयो और बहनो, भारत जिसके लिये जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उल्लेख भी करते हैं- विविधता में एकता, आज यह मंत्र अपनी पूर्णता के साथ खिला हुआ नज़र आता है, गर्व होता है। हज़ारों साल बाद भी किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का ज़रूर उल्लेख करेगा और यह घटना इतिहास के पन्नों से उठाई हुई नहीं है, सवा सौ करोड़ देशवासी खुद आज एक नया इतिहास रच रहे हैं, इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ रहे हैं।

साथियो, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते है परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती हैं। ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराएं हैं और इसलिए, देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली आज विशेष रूप से अभिनन्दन के अधिकारी हैं।

साथियो, आज 9 नवंबर है, 9 नवंबर ही वो तारीख थी, जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है- जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। इस विषय को, इन सारी बातों को लेकर कहीं भी, कभी भी, किसी के मन में कोई कटुता रही हो, तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है। नए भारत में भय, कटुता, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है।

साथियो, सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है, कानून के दायरे में ही आता है। हमें, इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है। हर परिस्थिति में भारत के संविधान, भारत की न्यायिक प्रणाली, यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।

साथियो, सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी, नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर, सबका विकास करते हुए और सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है।

साथियो, राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना, नियम-कायदों का सम्मान करना, ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है। अब समाज के नाते, हर भारतीय को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है।

हमारे बीच का सौहार्द, हमारी एकता, हमारी शांति, हमारा सद्भाव, हमारा स्नेह, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भविष्य की ओर देखना है, भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है। भारत के सामने, चुनौतियां और भी हैं, लक्ष्य और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। हर भारतीय, साथ मिलकर, साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, मंजिलों तक पहुंचेगा। मैं फिर एक बार आज 9 नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए, आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए, आप सबको आने वाले त्योहारों की, कल ईद का एक पवित्र त्यौहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद !

अयोध्या फैसले पर समाचार–पत्रों की सुर्खियां

असली मालिक रामलला, मंदिर यहीं बनेगा

– अमर उजाला

विवादित भूमि अब रामलला की, मस्जिद को अलग जमीन

– राजस्थान पत्रिका

राममंदिर का रास्ता साफ

– हिन्दुस्तान

मंदिर वहीं, मस्जिद नई

– नवभारत टाइम्स

रामजन्मभूमि पर मंदिर, वैकल्पिक जमीन पर मस्जिद बनाने के आदेश

– दैनिक ट्रिब्यून

मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद को जमीन

– राष्ट्रीय सहारा

वहीं बनेगा मंदिर

– दैनिक जागरण

विदेशी मीडिया की नजर में

श्रीराम जन्मभूमि से जुड़े भूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला पूरी दुनिया में सुर्खियां बना। इस फैसले पर विश्व के कई मुख्य अखबारों और न्यूज चैनलों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

भाजपा वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा करती रही है। ऐसे में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्टी की यह बड़ी जीत है।

-द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तानी समाचार पत्र

भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सालों से प्रचार करती आई है और अब मंदिर के पक्ष में फैसला आना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में एक बड़ी जीत होगी।

— अलजजीरा

दोबारा सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है। यह उनकी बड़ी कामयाबी है।

— द गार्जियन

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित भूमि पर मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को अलग से पांच एकड़ भूमि देने का भी आदेश दिया गया है।

— वाशिंगटन पोस्ट

भारतीय कोर्ट ने अयोध्या विवाद में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

— न्यूयॉर्क टाइम्स

इनका कहना है...

इस निर्णय से सिर्फ भारत की विजय हुई है। सौहार्द से साथ में रहने की हमारी भावना की जीत हुई है। भेदभाव हमारी साझा ऊर्जा और क्षमताओं का क्षय करता है। हमारी इस महान भूमि में सभी को समाहित करने की क्षमता है, सभी के लिए सम्मान है।

– **एम. वेंकैया नायडू,** उपराष्ट्रपति

मालिकाना हक सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है। 1856–57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सुबूत नहीं हैं। हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर सम्मान दिया गया है।

– **रंजन गोगोई,** मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्या में अब एक भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मंदिर निर्माण में सबका सहयोग हो। यह मंदिर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक बने। मुझे खुशी है कि आंदोलन के दौरान मुझे भी भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला था।

– **डॉ. मुरली मनोहर जोशी,** पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। अयोध्या पर दिया गया फैसला ऐतिहासिक और युगांतकारी है। यह किसी की हार या जीत का सवाल नहीं है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें।

– **राजनाथ सिंह,** केंद्रीय रक्षामंत्री

यह फैसला भारत की जीत है। यह हमारी न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक क्षण हैं। हम फैसले का सम्मान करते हैं। अब हम फिर से शांति, सौहार्द और समझदारी का संकल्प लें। शाश्वत मूल्यों और सांस्कृतिक विरासतों के बल पर अब देश आगे बढ़ेगा।

– **रविशंकर प्रसाद,** केंद्रीय कानून मंत्री

प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय विधि व्यवस्था की निष्पक्षता का सजीव प्रमाण है। सभी नागरिक इस फैसले को सहजता और सद्भाव के साथ स्वीकार करें।

– **योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री,** उत्तर प्रदेश

कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हम सबको आपसी सद्भाव बनाए रखना है। यह समय हम सभी भारतीयों के बीच आपसी भाईचारे, विश्वास और प्रेम का है।

– **राहुल गांधी,** पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

उच्चतम न्यायालय ने एक बेहद स्पष्ट और सर्वसम्मत फैसला किया है। एकमत से दिए गए इस फैसले में सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान किया गया। इससे उस विवाद का हल हो गया जो सदियों से अटका हुआ था। समूचा राष्ट्र इस फैसले का सम्मान करता है।

– **रामविलास पासवान,** लोजपा नेता

संविधान के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर आम सहमति से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। अब इस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आगे का काम होना चाहिए।

– **मायावती,** बसपा प्रमुख

यह निर्णय हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और रूल ऑफ लॉ तथा प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चूंकि पक्षकार निर्णय के बारे में पहले से कहते रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय जो भी होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा।

– **अखिलेश यादव,** राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा

कोर्ट ने जमीन हिंदू भाइयों को दे दी है और मुस्लिमों को अलग जमीन देने की बात कही है जहां वे मस्जिद बना सकते हैं। कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए और कौम और मुल्क में अमन शांति के लिए मुस्लिम पक्ष को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।

– **कल्बे सादिक,** शिया धर्मगुरु

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता है और पूरे देश को बधाई देता है। हम भी चाहते थे कि मंदिर बने।

– **सैयद वसीम रिजवी,** चेयरमैन, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड

दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

दीपावली के दिन 27 अक्टूबर को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की नई सरकार बनी। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता श्री मनोहर लाल खट्टर ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री और जजपा नेता श्री दुष्यंत चौटाला ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने पद की शपथ दिलाई।

गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती। सात निर्दलीय विधायकों के साथ 57 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य को सौंपा गया। सबसे पहले यू.टी. रेस्ट हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज ने श्री मनोहर लाल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वश्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्रीगण श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री आरएल कटारिया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व मुख्ययमंत्री एवं कांग्रेस नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख स. सुखबीर सिंह बादल सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।

गत 25 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार गठन को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और जननायक जनता पार्टी नेता श्री दुष्यंत चौटाला की बैठक हुई। इसके पश्चात् श्री शाह ने संवाददाताओं से कहा कि हरियाणा में मतदाताओं के जनादेश के साथ जाते हुए दोनों पार्टियों ने निर्णय किया है कि भाजपा और जजपा साथ मिलकर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री भाजपा से होगा जबकि उप मुख्यमंत्री जजपा से होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन जनादेश की भावना के अनुरूप है।

संवाददाता सम्मेलन में श्री शाह और श्री चौटाला के अलावा श्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। श्री चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि हरियाणा में स्थिरता के लिए गठबंधन जरूरी था।

श्री अमित शाह ने कहा कि अगले पांच साल तक मोदीजी के नेतृत्व में यहां विकास के लिए काम किया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में स्थायी सरकार बनाने के लिए वह भाजपा के साथ आए हैं। वहीं, श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा की भलाई के लिए हमने जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया है। ■

हरियाणा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी को बधाई। उन्हें हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करना है, जिसके लिए उन्हें शुभकामनाएं।

— **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं। साथ ही श्री दुष्यंत चौटाला को उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह जोड़ी हरियाणा के विकास को और अधिक गति प्रदान करेगी।

— **अमित शाह**, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

हरियाणा के विकास के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में श्री मनोहर लाल जी द्वारा किये गए कार्यों पर भरोसा दिखाने के लिए मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम हरियाणा की जनता की सेवा और उनके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई।

राज्य की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और विकासवादी नीतियों, राज्य की भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन वाली सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम राज्य में विकास की गति को और तीव्र करेंगे और हर व्यक्ति की सेवा करेंगे।

— **जगत प्रकाश नड्डा**
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

राज्य में शानदार काम कर रही है राजग सरकारः जेपी नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार की राजग सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार शानदार काम कर रही है। यहां केंद्रीय योजनाएं पूरी गंभीरता से जमीन पर उतर रही हैं। बिहार, केंद्र की टॉप प्रायोरिटी में है। केंद्र हर कदम पर बिहार के साथ खड़ा है।

श्री नड्डा 5 नवंबर को पटना में भाजपा नेता श्री कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर बदल चुकी है। गांवों में इसे खूब महसूस किया जा सकता है। विकास, सुदूर इलाकों में भी पहुंचा है। गड्ढा बनीं सड़कें चकाचक हुईं। राजग सरकार ने विकास की नई कहानी लिख दी। उन्होंने कहा- केंद्र, बिहार में बहुत बड़ी राशि खर्च कर रहा है। दरभंगा में दूसरा एम्स हर हाल में खुलेगा। 8 नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल समेत कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि स्व. कैलाशपति मिश्र पार्टी की प्रथम पीढ़ी के नेता थे। आज हम जहां हैं, उसकी नींव उन्हीं की रखी हुई है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्ता ही आगे बढ़ सकता है। ईमानदारी से काम करने वाला ऊपर तक जा सकता है। श्री नड्डा पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नगर मंत्री थे और आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह भाजपा में ही संभव है। मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। ■

भाजपा को लेह में 11,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मिला नया कार्यालय

अरुण सिंह ने पूजा के बाद पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन

भारतीय जनता पार्टी ने 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी लेह में एक नया कार्यालय खोला है। इस नए कार्यालय का उद्घाटन 7 नवबंर, 2019 को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह ने किया।

कार्यालय को सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से सीधे संवाद करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। एक असेंबली भवन भी बनाया गया है। श्री अरुण सिंह ने पूजा करने के बाद लेह में नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के भाजपा सांसद श्री जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल भी उपस्थित थे।

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू—कश्मीर को 31 अक्टूबर, 2019 के दो दिन केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसके बाद लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। लद्दाख में दो जिले हैः- लेह और कारगिल, जिनकी कुल आबादी 2,74,289 हैं। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य है। ■

जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हुआ

जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ''नयी व्यवस्था'' का लक्ष्य ''विश्वास की मजबूत कड़ी'' बनाना है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया और राज्य को विभाजित कर गठित किये गये दो नये केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया।

यह कदम पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उठाया गया है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्यों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए जम्मू-कश्मीर का उप राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को और लद्दाख का उप राज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया।

इस बीच, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये और लोगों को 'राष्ट्रीय एकता संकल्प' दिलाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रावधानों से राज्य में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही फैला। उन्होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नयी व्यवस्था का मतलब जमीन पर लकीर खींचना नहीं, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाना है।''

श्री मोदी ने कहा, ''पटेल ने एक बार कहा था कि यदि उनके (पटेल के) हाथों में कश्मीर मुद्दा होता, तो इसका हल करने में इतना लंबा समय नहीं लगता।''

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के प्रवेश द्वार थे। मोदी ने इन्हें रद्द कर इस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिये जम्मू-कश्मीर राज्य की जगह 'जम्मू-कश्मीर संघ राज्य प्रदेश' शब्दावली का उल्लेख किया गया। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। ■

कश्मीर पहुंचे यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा

अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला

जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों ने 30 अक्टूबर को कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह देश के साथ खड़े हैं।

फ्रांस के हेनरी मेलोसे ने कहा, ''अनुच्छेद 370 की बात करें, तो यह भारत का आंतरिक मामला है। हमारी चिंता का विषय आतंकवाद है जो दुनिया भर में परेशानी का सबब है और इससे लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। मेलोसे ने कहा कि दल ने सेना और पुलिस से बात की है। युवा कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत हुई तथा अमन कायम करने के विचारों का आदान-प्रदान हुआ। पोलैंड के सांसद रेजार्ड जारनेकी ने कहा, ''ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने जो दिखाया वह पक्षपातपूर्ण था। हमने जो देखा है, अपने देश लौटकर हम उसकी जानकारी देंगे।'' ब्रिटेन के न्यूटन डन ने इसे 'आंखे खोलने वाला दौरा' बताया। डन ने कहा, ''हम यूरोप से आते हैं, जो वर्षों के संघर्ष के बाद अब शांतिपूर्ण स्थान है। हम भारत को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनता देखना चाहते हैं। इसके लिए जरूरत है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े रहें। यह दौरा आंखें खोलने वाला रहा है और जो कुछ हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है हम उस पर अपनी बात रखेंगे।''

फ्रांस के ही एक अन्य सांसद थियेरी मारियानी ने मीडिया को बताया कि वह पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं और यह दौरा भारत के आंतरिक मामले में दखल देने के लिए नहीं है, बल्कि कश्मीर में जमीनी हालात के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए किया गया है।

उन्होंने कहा, ''आतंकवादी एक देश को बरबाद कर सकते हैं। मैं अफगानिस्तान और सीरिया जा चुका हूं और आतंकवाद ने वहां जो किया है वह देख चुका हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं।''

यूरोपीय संसद के इन सदस्यों ने अपनी दो दिवसीय कश्मीर यात्रा के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नयी दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इनका स्वागत करने के साथ उम्मीद जताई थी कि जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में उनकी यात्रा सार्थक रहेगी।

पीएमओ ने एक बयान जारी करके कहा, ''जम्मू-कश्मीर के इस दौरे से शिष्टमंडल को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वे इस क्षेत्र के विकास एवं शासन से संबंधित प्राथमिकताओं की सही स्थिति से अवगत होंगे।'' राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने भी शिष्टमंडल को जम्मू-कश्मीर के हालात की जानकारी दी थी। उन्होंने मेहमानों के लिए दोपहर के भोज का आयोजन भी किया था। ■

करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पित

15 एकड़ जमीन पर शानदार यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर को गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे और यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यात्री टर्मिनल को एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) भी कहा जाएगा। तीर्थयात्री 4.5 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित गलियारे (करतारपुर कॉरिडोर) से जाने के लिए यहीं से मंजूरी प्राप्त करेंगे, जो भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा।

करतारपुर गलियारे की चैक पोस्ट के शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

उल्लेखनीय है कि डेरा बाबा नानक के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जीरो-प्वॉइंट पर करतारपुर साहेब गलियारा तैयार करने के लिए भारत ने 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। स्मरण रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में और पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक 550वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप में मनाने के लिए 22 नवम्बर, 2018 को प्रस्ताव पारित किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहेब गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी, ताकि पूरे वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहेब करतारपुर जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

- डेरा बाबा नानक को अमृतसर-गुरदासपुर राजमार्ग से जोड़ने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन वाला 4.2 किलोमीटर लम्बा राजमार्ग बनाया गया।
- 15 एकड़ जमीन पर शानदार यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है, यह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसका निर्माण हवाई अड्डे की तरह किया गया है। यहां 50 आव्रजन काउंटर हैं, जो प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करेंगे।
- मुख्य इमारत में शौचालय, सहायता केंद्र, बच्चों के लिए सुविधा, प्राथमिक उपचार सुविधा, प्रार्थना कक्ष, अल्पाहार काउंटर आदि मौजूद हैं।
- मजबूत सुरक्षा के लिए सीसीटीवी द्वारा निगरानी की व्यवस्था है तथा जन सूचना प्रणाली लगाई गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 300 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है।

प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा बेर साहिब में मत्था टेका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से 9 नवंबर को सुलतानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब में मत्था टेका। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, पंजाब के राज्यपाल श्री बी पी सिंह बदनौर तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ थे।

गुरुद्वारे के मुख्य परिसर में प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की। गुरुद्वारे के ग्रंथियों ने प्रधानमंत्री को एक शॉल भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने उस बेर पेड़ को भी देखा, जिसके नीचे श्री गुरू नानक देव जी ने 14 वर्षों तक ध्यान लगाया था।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- सभी धर्मों को मानने वाले भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालु गलियारे का उपयोग कर सकते हैं।
- यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है।
- श्रद्धालुओं के पास केवल वैधानिक पासपोर्ट होना चाहिए।
- भारतीय मूल के लोगों के लिए अपने देश के पासपोर्ट के साथ ओसीआइ कार्ड रखना आवश्यक होगा।
- गलियारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। सुबह जाने वाले श्रद्धालुओं को उसी दिन वापस लौटना होगा।
- केवल अधिसूचित दिनों को छोड़कर गलियारा पूरे साल खुला रहेगा, जिसकी सूचना अग्रिम रूप से दे दी जाएगी।
- श्रद्धालुओं को अकेले या समूह में अथवा पैदल जाने की छूट होगी।
- यात्रा तिथि के 10 दिन पहले भारत श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान को सौंपेगा। यात्रा तिथि के 4 दिन पहले श्रद्धालुओं को यात्रा की पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाएगी।
- पाकिस्तान पक्ष ने भारत को आश्वासन दिया है कि 'लंगर' और 'प्रसाद' का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा। ■

4.58 लाख अधूरे फ्लैटों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी

1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मिलेगी मदद

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर को 4.58 लाख अधूरे फ्लैटों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी। 10 हजार करोड़ रुपए सरकार देगी और 15 हजार करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक एवं एलआईसी देंगे।

यह कोष उन डेवलपर्स को राहत प्रदान करेगा, जिन्हें अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदने वालों को घरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। दरअसल, रियल एस्टेट उद्योग आंतरिक रूप अनेक अन्य उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, 'अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार, एसबीआई, एलआईसी वैकल्पिक निवेश कोष के लिए 25,000 करोड़ रुपए देंगी।'

वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा। चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन चुकी आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि माननीय वित्तमंत्री ने 14 सितंबर, 2019 को यह घोषणा की थी कि किफायती और मध्यम-आय वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए एक स्पेशल विंडो स्थापित की जाएगी, जो रूकी पड़ी सभी आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी।

परिणामस्वरूप आवासीय वित्त कंपनियों, बैंकों, एनबीएफसी, निवेशकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स सहित आवास उद्योग के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनेक हितधारक परामर्शों का आयोजन किया गया। घर क्रेताओं, डेवलपर्स, लेंडर्स और निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाया गया और उनका स्पेशल विंडो के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। ■

वित्तीय समावेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करने वाले शीर्ष देशों में भारत

भारत वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष देशों में है। 31 अक्टूबर को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने गैर बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति दी है, अनुपातिक उपभोक्ता जांच पड़ताल और प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण का माहौल दिया है।

'द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन रिपोर्ट' में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को लेकर माहौल में सुधार हुआ है। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से भारत, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे और मेक्सिको ने वित्तीय समावेशन के लिए सबसे अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन के लिए चार मूल चीजों की जरूरत है। ये हैं..गैर बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति, वित्तीय सेवा एजेंटों की उपस्थिति, अनुपातिक आधार पर ग्राहक जांच परख और प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण।

इन सभी चार मानदंडों पर सिर्फ चार देशों कोलंबिया, भारत, जमैका और उरुग्वे ने पूरे अंक हासिल किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ दक्षिण अफ्रीका, भारत, मेक्सिको, तंजानिया और उरुग्वे ई-मनी को जमा बीमा या संरक्षण के जरिये रक्षोपाय उपलब्ध कराते हैं।

रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के संरक्षण से नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वालों को सुरक्षा मिलती है और विभिन्न प्रकार के संस्थानों के बीच नियामकीय असंतुलन पैदा नहीं होता है। साथ ही डिजिटल वित्तीय समावेशन से यह भी सुनिश्चित होता है कि वित्तीय प्रणाली में नए ग्राहकों को परंपरागत संस्थानों के साथ लेनदेन करने की तुलना में नुकसान नहीं होता। ■

यह मेरा नहीं सबका है और इसलिए राष्ट्र का है

दीनदयाल उपाध्याय

गोली का पहला शिकार लोकतंत्रवादी होगा

आज समाजवादी खेमे में व्याप्त भ्रमपूर्ण स्थिति के लिए बहुत अंशों तक यह सिद्धांत ही जिम्मेदार है, अब तक कोई भी विचारक ऐसा सर्वांगपूर्ण दोषरहित चित्र प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सका है, जिसमें इन दोनों तत्वों का सह अस्तित्व संभव हो सके। इसमें भी, यदि हम लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों और मर्यादाओं के साथ-साथ भिन्न-भिन्न देशों के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे और भिन्न-भिन्न प्रकार के भौतिक एवं आर्थिक विकास के स्तरों पर विचार करें, तब तो यह भ्रम के बादल और भी घनीभूत हो जाते हैं। इस भ्रजमाल की जटिलता के कारण यह गुत्थी इतनी उलझती जाती है कि जिसका सुलझना असंभव सा हो जाता है।

गैर-समाजवादी देशों ने भी समाजवादियों के भ्रम को बढ़ाने का ही कार्य किया है। विगत 30 वर्षों में अपनी उदारवादी नीतियों एवं नवीन आर्थिक चिंतन के कारण उन्होंने समाजवादियों को हतप्रभ सा कर डाला है। आज अमरीका या इंग्लैंड का सर्वसाधारण व्यक्ति, किसान और मज़दूर, जिसे साम्यवादी परिभाषा के अनुसार सर्वहारा कहा जाता है, सौ वर्ष पूर्व की उत्पीड़ित अवस्था में नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रस्थापित हो रहे हैं। पूंजीवादी ओर समाजवादी दोनों ही प्रकार के देशों के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई है। कल के पूंजीवादी देशों ने अपनी पद्धति में विकास किया है और आज वे भौतिक विकास में समाजवादियों से टक्कर लेने को उद्यत हैं, पर समाजवाद आज भी उसी स्थान पर ही अड़ा हुआ है, जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यदि उसने कुछ पग आगे बढ़ाए भी हैं तो वे सही दिशा में नहीं बढ़े हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र होने के कारण अपनी भूलों को सुधारने एवं नवीन बातों को स्वीकार करने की सिद्धता रहती है। पर समाजवादियों के समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में इस प्रकार के लचीलेपन का अभाव है। यह विचारधारा किसी प्रकार के नवीन चिंतन की प्रेरणा नहीं देती। मसीहावाद और अपरिवर्तनीय अंधविश्वासों पर आधारित मज़हब के अनुयायी की तरह कट्टर समाजवादी नए स्वतंत्र विचारों से दूर ही रहना पसंद करता है। यही कारण है कि कम्युनिस्टों के शब्दकोश में ऐसे विचारकों के लिए अनेक प्रकार की गालियां भरी रहती हैं। परंतु विचारशील मानव विचाररहित नहीं हो सकता। यदि उसकी विचार-तंरगों को योग्य दिशा देने की कोई योजनाबद्ध व्यवस्था न रही तो उसका अनिवार्य परिणाम चतुर्दिक भ्रम के रूप में सामने आए बिना नहीं रह सकता।

यह कैसा विरोध?

आज भारत में समाजवाद के बारे में जो वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है, वह प्रमुख रूप से राजकीय उद्योगों के विस्तार की अनिवार्यता या व्यर्थता के ऊपर ही केंद्रित है। स्वतंत्र उद्योगों के पुरस्कर्ता एवं समाजवादी विचारक एक-दूसरे के विरुद्ध ताल ठोककर खड़े हो गए हैं। पर साथ ही एक मजेदार तथ्य यह है कि दोनों एक-दूसरे के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत क्षेत्र को ख़ाली छोड़ने के लिए तत्पर भी हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था में सरकार को कुछ ऐसे उद्योगों को भी अपने हाथ में लेना पड़ता है, जो कदाचित् साधारण अवस्था में स्वतंत्र लोगों के हाथ में छोड़े जा सकते थे। साथ ही किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र उद्योगपतियों को वैसी खुली छूट भी नहीं दी जा सकती, जैसी शताब्दियों से पश्चिम के लोग उपयोग करते रहे हैं। सच पूछा जाए तो यह स्पर्धा यदि नियंत्रित रखी गई, तो दोनों में योग्य संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकती है। समस्याओं का सामना करते समय समाजवादी स्वतंत्रों की श्रेणी में आ बैठता है और स्वतंत्र समाजवादी खेमे में।

साध्य के अनुरूप साधन हों

पर प्रमुख समस्या यह नहीं है कि हम समाजवाद को स्वीकार करें या उद्योगों की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को। समाजवाद और लोकतंत्र की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, पर हमारे लिए ये ही विकल्प के रूप में नहीं हैं। वे साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। तब फिर साध्य क्या हो? हमें पहले गंतव्य निर्धारित कर, फिर मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। सभी विचारशील मनुष्यों ने मानव कल्याण को साध्य माना है। पर दुर्भाग्य यह है कि अभी तक मनुष्य मनुष्य को ही समझने में असमर्थ रहा है। मानव को सुखी व संपन्न बनाने के प्रयास में समाजवाद एवं लोकतंत्र. दोनों ने ही उसको एक वीभत्स स्वरूप दे डाला है। उन्होंने उसकी समस्त विशेषताओं को उससे छीन लिया है। रेने फुलप ने 'डी ह्यूमनाइजेशन इन मॉर्डन सोसाइटी' (De-Humanisation in modern society) नामक अपनी पुस्तिका में लोकतंत्र एवं समाजवाद के इस पहलू का

विशद् विवेचन किया है। वह लिखता है

'Democracy, although it gave us right to vote, trial by jury, a free press, religious freedom, the freedom to choose their jobs and the freedom to speak their mind, it also gave us the economic man.'

(यद्यपि जनतंत्र ने हमें मत देने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, विचार स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, स्वयं का पेशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता और भाषण स्वातंत्र्य प्रदान किया है, पर साथ ही उसने हमें एक 'आर्थिक मानव' की कल्पना भी दी है।)

इस कल्पना ने पूंजीवाद को जन्म दिया, जहां अधिकाधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर तो अत्यधिक बल दिया गया, पर सोद्देश्य जीवन व्यतीत करने की क्षमता बढ़ाने की ओर पूर्ण दुर्लक्ष्य कर दिया गया। दूसरी ओर समाजवाद या साम्यवाद ने सामूहिक सुरक्षा एवं मज़दूर वर्ग के हितों के संरक्षण का नारा लगाया, पर इसी के साथ-साथ उसने 'युद्ध-पिपासु मानव' को जन्म दिया। यह युद्ध-लोलुप मानव समाजवादी राज्य की ही देन है। उसे न विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, न स्वयं के निर्णय करने की। इस व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन का मूल्य एक निरीह पशु से अधिक नहीं आंका जाता।

मशीन की गुलामी का अंत आवश्यक

समाजवाद और लोकतंत्र दोनों ने ही मानव के भौतिक स्वरूप और आवश्यकताओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है और दोनों की आधुनिक विज्ञान तथा यांत्रिक उन्नति पर अत्यधिक श्रद्धा है। दोनों ही इन वर्तमान आविष्कारों के शिकार से हो गए हैं। परिणाम यह है कि उत्पादन के साधनों का निर्धारण मानव कल्याण और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनका निर्धारण यंत्रों के अनुसार करना पड़ रहा है। उत्पादन की केंद्रित व्यवस्था में, फिर उसका नियंत्रण चाहे व्यक्ति द्वारा हो अथवा राज्य द्वारा, मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व का लोप हो जाता है। मशीन के एक पुरज़े से अधिक उसका महत्त्व ही नहीं रहता। यदि हमें मनुष्य के मनुष्यत्व की रक्षा करनी है तो उसे मशीन की गुलामी से मुक्त करना होगा।

आज व्यक्ति मशीन पर शासन नहीं करता, मशीन मनुष्य पर शासन कर रही है। इस मशीन-प्रेम के मूल में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को अधिकाधिक मात्रा में तृप्त करने की भावना ही निहित है। पर हम यह न भूलें कि केवल भौतिक समृद्धि मात्र से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। भौतिक साधनों से संपन्न राष्ट्रों की समस्याएं भी आज हमारे सम्मुख हैं। हमें संपूर्ण मानव जीवन का विचार कर उत्पादन, वितरण और उपभोग को एक इकाई मानकर चलना पड़ेगा। हमें एक ऐसी पद्धति का निर्माण करना होगा, जिसमें मनष्य उत्पादन और उपभोग करते समय एक सार्थक जीवन व्यतीत करने का भी ध्यान रखता है। मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं का समुच्चय मात्र ही नहीं है। उसकी कुछ आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। जो जीवन-पद्धति मानव-जीवन के इस आध्यात्मिक पहलू की उपेक्षा करती हो, वह कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। यहां हमें इस बात का स्मरण रखना होगा कि भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक प्रगति की कल्पना केवल हवाई उड़ान ही नहीं है। मानव की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का दायित्व भी निभाना ही होगा। समाजवाद और लोकतंत्र दोनों ने ही एकांगी मार्ग स्वीकार किया है और मनुष्य की इन दो भिन्न प्रवृत्तियों का समुचित सामंजस्य बिठाकर उसके व्यक्तित्व का विकास करने के स्थान पर एक भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर विभिन्न शक्तियों के लिए एक युद्ध-स्थल तैयार कर दिया है।

तरणोपाया

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों पर आधारित हिंदू जीवनादर्श ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। विश्व की समस्याओं का उत्तर समाजवाद नहीं, हिंदुत्ववाद है। यही एक ऐसा जीवन दर्शन है, जो जीवन का विचार करते समय उसे टुकड़ों में नहीं बांटता अपितु संपूर्ण जीवन को एक इकाई मानकर उसका विचार करता है। यहां पर हमें हिंदू-जीवनादर्शों का विचार करते समय कुछ निष्प्राण कर्मकांड के साथ अथवा हिंदू समाज में व्याप्त अनेक अहिंदू व्यवहारों के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही यह समझना भी भारी भूल होगी कि हिंदुत्व वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का विरोधी है। विज्ञान और यंत्र इन दोनों का उपयोग इस पद्धति से होना चाहिए, जिससे वे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पद्धति के अनुरूप हों।

महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण कर विनोबा, जयप्रकाश नारायण और राजगोपालाचारी ने ट्रस्टीशिप का विचार सम्मुख रखा है। यह हिंदू जीवन-पद्धति के अनुसार ही है। यह एक ऐसा विचार है, जो समाजवादी और गैर-समाजवादी दोनों ही समाजों के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकता है। पर यदि हम पाश्चात्य-यंत्र प्रणाली का अंधानुकरण करते रहे तो पूंजीवाद या समाजवाद दोनों ही न हमारी संस्कृति का संरक्षण कर सकेंगे और न हमारे सम्मुख उपस्थित समस्याओं का समाधान ही कर सकेंगे। हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैद्धांतिक सभी मोरचों पर इस यंत्रवाद का सामना करना पड़ेगा। हमें धर्मराज्य, लोकतंत्र, सामाजिक समानता और आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपना लक्ष्य बनाना होगा। इन सबका सम्मिलित निष्कर्ष ही हमें एक ऐसा जीवन-दर्शन उपलब्ध करा सकेगा, जो आज के समस्त झंझावातों में हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। आप इसे किसी भी नाम से पुकारिए, हिंदुत्ववाद, मानवतावाद अथवा अन्य कोई भी नया वाद, किंतु यही एकमेव मार्ग भारत की आत्मा के अनुरूप होगा और जनता में नवीन उत्साह संचारित कर सकेगा। संभव है, विभ्रांति के चौराहे पर खड़े विश्व के लिए भी यह मार्गदर्शक का काम कर सके। ■

-पाञ्चजन्य, दिसंबर 5, 1960

'राजनीति के अजातशत्रु' कैलाशपति मिश्र

(5 अक्टूबर 1923 - 3 नवंबर 2012)

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री कैलाशपति मिश्र को बिहार भाजपा का 'भीष्म पितामह' कहा जाता है। श्री मिश्र का जन्म बक्सर जिले में दुधारचक गांव में 5 अक्तूबर, 1923 को हुआ था। 1942 के 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में 10वीं के छात्र रहते हुए जेल गए। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, तो फिर अपने राष्ट्र और समाज की सेवा ही उनका ध्येय बन गया।

संघ प्रचारक के रूप में आरा से सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, 1947 से 52 तक पटना में प्रचारक रहे, 1952 से 57 तक पूर्णिया के जिला प्रचारक रहे, फिर संघ के निर्देश पर ही जनसंघ में गए। 1959 में जनसंघ के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व मिला, तो आपातकाल के बाद चुनावी राजनीति में उतरने के निर्देश का भी पालन किया। विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े, जीते और कर्पूरी

ठाकुर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे।

1980 में जनसंघ के नए रूप में सामने आयी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के वे पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए। फिर 1983 से 1987 तक निर्वाचित अध्यक्ष रहे। इस बीच 1984 से 1990 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही अनेक राज्यों के संगठन मंत्री का दायित्व भी उन्होंने बखूबी निभाया। 7 मई, 2003 से 7 जुलाई, 2004 तक वे गुजरात के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। इसी दौरान 4 माह के लिए राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार भी उन पर था।

50 वर्ष से अधिक लम्बी चली उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा में न उन पर कोई आरोप लगा और न ही वे किसी विवाद का अंग बने। राजनीति की दलदल में कमल के समान अहंकार, बुराई, द्वेष, लोभ-लालच आदि सामान्य दोषों से भी अछूते रहने वाले कैलाशपति अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए आज भी आदर्श एवं प्रेरणास्रोत हैं।

श्री कैलाशपति मिश्र एक साहित्यकार भी थे। इनकी लिखी पुस्तकों में 'पथ के संस्मरण' (आत्मकथा) और 'चेतना के स्वर' (कविता संग्रह) प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 3 नवंबर 2012 को पटना में हुई। ■

पंजाब के पूर्व भाजपा अध्यक्ष कमल शर्मा का निधन

(17 मार्च 1970 - 27 अक्टूबर 2019)

पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री कमल शर्मा का 27 अक्टूबर को फिरोजपुर (पंजाब) में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। 17 मार्च 1970 को पंजाब के फिरोजपुर में पैदा हुए श्री शर्मा भाजपा राष्ट्रीयकारिणी के सदस्य थे। श्री शर्मा 1985 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 2013 को उन्होंने भाजपा के पंजाब अध्यक्ष का दायित्व संभाला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कमल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट में लिखा कि कमल शर्मा के निधन से बेहद दुःख हुआ। पंजाब में पार्टी की मजबूती के लिए कमल शर्मा ने अमूल्य योगदान दिया। दुःख की इस घड़ी में मेरी

संवेदना उनके परिवार व पार्टी समर्थकों के साथ है। ॐ शांतिः।

केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने श्री शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट में लिखा कि पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री कमल शर्मा जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुःखी हूं। कमल जी ने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति के प्रदान करे। ॐ शांति शांति शांति

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री कमल शर्मा के निधन पर शोक जताया किया और ट्वीट में लिखा कि मेरे मित्र, भाजपा (पंजाब) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री कमल शर्मा जी के आकस्मिक निधन से मैं शोक स्तब्ध हूं। उनका निधन संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें व शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांतिः। ■

कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल के योगदान को हमेशा याद रखेगाः अमित शाह

सरदार पटेल ने देश को एक करने का काम किया

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई कि 'मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश दिलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं।'

श्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल के कारण अखंड भारत का अस्तित्व सामने आया, उन्होंने भारत को एक करने का काम किया, इसलिये आज एकता दिवस पर हम सरदार पटेल को याद कर देश को अखंडित रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हमारे सामने जो एक भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है वह सरदार पटेल के कारण ही दिखाई दे रहा है। देश को आजाद करते समय अंग्रेजों ने देश को रियासतों में बांटने का काम किया था, उनका मानना था कि भारत को आजादी तो मिली थी किंतु कई टुकड़ों में।

श्री शाह ने कहा कि उस समय जब यह समस्या उठाई गई कि 550 टुकड़ों में एक देश कैसे पनप सकता है, कैसे विकसित हो सकता है तब महात्मा गांधी ने निर्णय किया कि देश की सभी रियासतों को एक संघ राज्य भारत बनाने का काम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के द्वारा किया जाएगा। उसी दिन से सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ जब तक पूरा देश एक नहीं हुआ तब तक सभी रियासतों को जोड़ने का काम किया। तत्कालीन समय में कई प्रकार की दिक्कतें भी आईं, किंतु सरदार पटेल ने एक भारत बनाने का काम किया और भारत को वर्तमान स्वरूप दिया।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि आपके अलावा और कोई इस कार्य कों नहीं कर सकता था तथा आपने देश को एक कर भारत की सबसे बड़ी सेवा करने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि आज की एकता दौड़, देशवासियों की एकता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है और देशभर में इसी समय हर नगर में, हर शहर में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जो सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि एकता दौड़ की शुरुआत उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एक करने का काम किया, किंतु एक कसक छूट गई थी जो जम्मू कश्मीर के रूप में थी। जम्मू कश्मीर का विलय तो भारत में हुआ किंतु धारा 370 और 35 ए के कारण यह समस्या बन गई थी।

श्री शाह ने कहा कि 70 साल तक किसी ने भी धारा 370 को छूना भी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब देश की जनता ने 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दोबारा सत्ता सौंपी तब धारा 370 और 35 ए को हटाने का साहसिक कदम लिया गया और सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा किया गया। श्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 व 35ए को निकालकर कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि धारा 370 एवं 35 ए आतंकवाद का गेटवे बनी हुई थी जिसे रोकने का काम श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। श्री अमित शाह ने कहा कि देश की आजादी के कई सालों बाद भी सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया गया और सरदार पटेल को भुलाने के प्रयास किए गए, किंतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में देश के करोड़ों किसानों से अपने खेत में उपयोग किया जा चुका लोहा मांगने का काम किया और देश भर के करोड़ों किसानों के पास से लोहा, गांव से मिट्टी तथा नदियों का जल मंगा कर गुजरात में एक अद्भुत स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने 182 मीटर ऊंचे इस स्टेच्यू को बनाकर सरदार साहब को उचित सम्मान देकर विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने के बाद 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनामी बनकर दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र की सूची में शामिल हो जाएगा। श्री शाह ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। ■

राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनाराः आरसेप में भारत को कमजोर करने के बीज कांग्रेस सरकार ने बोए थे

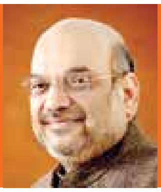

अमित शाह

भारत ने रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप को खारिज कर दिया और इस तरह 4 नवंबर, 2019 की तारीख भारत के व्यापारिक समझौता वार्ताओं के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। आज का भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने वाला भारत है। पहले के मुकाबले देश में एक नई ऊर्जा का प्रवाह है। इस ऊर्जा के सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। आरसेप प्रस्ताव को नकारने का मर्म प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में समाहित है, 'जब मैं सभी भारतीयों के हितों के संबंध में आरसेप समझौते को मापता हूं तो मुझे सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। न तो गांधीजी की नीति (स्वदेशी) और न ही मेरा विवेक मुझे आरसेप में शामिल होने की अनुमति देता है।'

मोदी जी ने की देश के किसानों, उद्योगों के हितों की रक्षा

इस निर्णय से मोदी जी ने देश के किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, कपड़ा व्यापार, डेयरी और विनिर्माण क्षेत्र, दवा, इस्पात और रासायनिक उद्योगों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ भारत का पक्ष विश्व के बड़े नेताओं के समक्ष रखा और तब तक इस समझौते में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, जब तक भारत के व्यापारिक घाटे, डंपिंग और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों पर सहमति नहीं बन जाती।

संप्रग सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों की रक्षा करने में असफल रही

मेरा मानना है कि भारत को किसी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय करार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो एकतरफा हो और जिसमें भारत के किसानों और उद्यमियों के हितों से समझौता किया गया हो, मगर बड़े दुःख की बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही। 2007 में कांग्रेस सरकार ने चीन के साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौता यानी आरटीए पर विचार करना शुरू कर दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने कितना नुकसान पहुंचाया, यह इससे प्रमाणित होता है कि चीन से भारत का व्यापार घाटा उसके कार्यकाल में 23 गुना बढ़ा। 2005 में भारत का यह घाटा 1.9 अरब डॉलर था। वहीं 2014 में यह बढ़कर 44.8 अरब डॉलर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे स्थानीय उद्योगों को कितना भारी नुकसान हुआ होगा।

> **"मेरा मानना है कि भारत को किसी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय करार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो एकतरफा हो और जिसमें भारत के किसानों और उद्यमियों के हितों से समझौता किया गया हो।"**

अंतरराष्ट्रीय दबाव में समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा

अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीय किसानों और उद्योगों के हितों से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। 2013 का बाली समझौता इसका उदाहरण है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बाली में हुई डब्ल्यूटीओ बैठक में देश को कृषि सब्सिडी और कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य देने के प्रावधान को कमजोर करने की राह पर डाल दिया। जब 2014 में निजाम बदला तब पीएम मोदी के निर्देश पर तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर देश के किसानों का भविष्य सुरक्षित किया।

आरसेप में भारत के पक्ष को कमजोर करने के बीज कांग्रेस सरकार में बोए गए थे

आरसेप से बाहर आने के हमारे राष्ट्रहित के फैसले का कांग्रेस नेता यह कहकर श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि यह उनके दबाव से संभव हुआ। इतिहास साक्षी है कि आरसेप में भारत के पक्ष को कमजोर करने के बीज कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही बोए गए थे।

आरसेप में शामिल होने से व्यापारियों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता

शुरुआती स्तर पर आरसेप में दस सदस्यीय आसियान देशों के अलावा केवल चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के शामिल होने की योजना थी, मगर अति उत्साह की शिकार कांग्रेस सरकार ने आरसेप संबंधी वार्ता को मंजूरी दी, जबकि यह स्पष्ट था कि यह चीनी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने का दरवाजा है। भारत का इन देशों के साथ भारी व्यापार घाटा है, फिर भी कांग्रेस सरकार ने आरसेप में शामिल होना उचित समझा। इसका हमारे छोटे व्यापारियों, दुग्ध उत्पादकों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित था।

कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों को किया दरकिनार

इससे पहले कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों को आसियान-एफटीए समझौते में भी दरकिनार किया। भारत ने लगभग 74 प्रतिशत वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोलने का निर्णय लिया, जबकि इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने भारत के लिए मात्र 50 प्रतिशत और 69 प्रतिशत तक ही अपना बाजार खोला। इसका नतीजा रहा कि भारत का आरसेप देशों से व्यापारिक घाटा, जो 2004 में सात अरब डॉलर था, 2014 आते-आते 78 अरब डॉलर पहुंच गया।

मोदी सरकार ने कांग्रेस की गलतियों को सुधारने का किया प्रयास

अपनी खराब नीतियों के चलते कांग्रेस ने आरसेप की शुरुआत में ही कई गलत प्रस्ताव स्वीकार कर लिए थे। 2014 से ही मोदी सरकार ने कांग्रेस की गलतियों को सुधारने का अथक प्रयास किया। तबसे भारत आरसेप समझौता वार्ता में लगातार अपने हितों की रक्षा करता रहा और अपनी तमाम मांगें मनवाईं। जैसे पहली बार सेवा क्षेत्र भारत के लिए खोला गया। इससे भारतीयों के लिए इन देशों में रोजगार के अवसर मिलने की राह खुली। भारत को बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों के निर्यात का मौका भी मिला। साथ ही निवेश संबंधी प्रस्ताव भी भारतीय मांग के अनुरूप मंजूर किए गए।

आरसेप में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने जो इंपोर्ट ड्यूटी लागू थी उसे ही बेस रेट मान लिया

आरसेप में शामिल होने के लिए कांग्रेस इतनी अधीर थी कि उसने 2016 तक समझौता लागू होने के अनुमान से यह तय कर लिया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी 1 जनवरी, 2014 को लागू थी, उसे ही बेस रेट मान लिया जाए। इसका परिणाम यह होता कि जब भी आरसेप लागू होता तब भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटी होती वह इन देशों के आयात पर (जो हमारे घरेलू उद्योगों का संरक्षण करती है) घटकर 2014 के स्तर पर लागू होती। इससे आयात बढ़ता और भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान होता।

मोदी सरकार की मांग है इंपोर्ट ड्यूटी के लिए 2019 को ही आधार वर्ष बनाया जाए

इस बीच हमारी एक मुख्य मांग यह रही कि मौजूदा हालात को देखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी के लिए 2019 को ही आधार वर्ष बनाया जाए। हालिया आरसेप बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय किसानों, डेरी उद्योग, लघु/मध्यम और विनिर्माण उद्योग के हितों को आधार बनाकर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा। इस वार्ता में राष्ट्र हित से जुड़े तमाम अहम मुद्दे उठाए गए। जैसे टैरिफ डिफरेंशियल में संशोधन, सीमा शुल्क की आधार दर में बदलाव, मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम का उन्मूलन, संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश को एक विशेष नियम से बाहर रखना, निवेश प्रक्रिया में भारत के संघीय ढांचे के महत्व का सम्मान आदि। वास्तव में इस वार्ता के एजेंडे में शामिल 70 में से 50 बिंदु भारत के थे।

भारत ने आसियान समझौते और सेपा समझौते की समीक्षा शुरू कर दी

फिलहाल भारत ने आसियान समझौते और दक्षिण कोरिया के साथ सेपा समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है। हम जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों के साथ निकट भविष्य में समझौते करने वाले हैं। इनसे देश के किसानों, लघु-मध्यम उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र को भारी लाभ होगा। इससे देश को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक आरसेप का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भारत को जिस तरह स्थापित कर रहे हैं उसे देखते हुए आरसेप में हमारी मांगों की लंबे अर्से तक अनदेखी नहीं की जा सकती। एफटीए के जरिये आसियान के साथ हमारा व्यापार प्रगति पर है। वहीं, आरसेप को खारिज करके हमने चीन के संभावित नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर दिया है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

"जहां तक आरसेप का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भारत को जिस तरह स्थापित कर रहे हैं उसे देखते हुए आरसेप में हमारी मांगों की लंबे अर्से तक अनदेखी नहीं की जा सकती। एफटीए के जरिये आसियान के साथ हमारा व्यापार प्रगति पर है। वहीं, आरसेप को खारिज करके हमने चीन के संभावित नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर दिया है।"

ईमानदार व पारदर्शी भाजपा सरकार के चलते हरियाणा में हमें पुनः जनसमर्थन मिलाः अनिल जैन

हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। राज्य में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और बहुमत से थोड़ी ही दूर रही। ध्यातव्य हो कि हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से भाजपा ने 40 सीटों पर विजय हासिल की थी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन से उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर कमल संदेश के सहायक संपादक संजीव सिन्हा ने बातचीत की। डॉ. जैन का कहना है कि हरियाणा में भाजपा की ईमानदार और पारदर्शी सरकार के चलते पार्टी को दुबारा जनसमर्थन मिला। वहीं उनका मानना है कि मोदी शासन में विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर हम सशक्त हो रहे हैं और गरीब अपने दम पर खड़ा हो सके, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

हम यहां बातचीत के मुख्यांश प्रस्तुत कर रहे हैं :

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक सीटें जीती। पांच साल शासन में रहने के बाद लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करना कठिन होता है। पार्टी बहुमत के करीब रही। इस उपलब्धि के पीछे क्या कारण रहे?

देखिए, हरियाणा विधानसभा में पहले हम 4 से 47 हुए। इस चुनाव में हमें 40 सीटें मिलीं। यह उपलब्धि हम इसलिए प्राप्त कर पाए कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। मोदीजी की अपार लोकप्रियता है। इसके साथ, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और प्रदेश भाजपा ने अच्छी रणनीति बनाई। हमने इसे नीचे तक क्रियान्वित किया। इसका हमें लाभ मिला। सांगठनिक स्तर पर विजय संकल्प रैली, पन्ना प्रमुख महासम्मेलन, चुनावी जनसभा, सघन प्रवास और संवाद आदि के माध्यम से संगठन को सशक्त करते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की।

राज्य सरकार के सुशासन से लोगों में बहुत उत्साह था। इसी के कारण हमने पांच वर्षों में जो भी चुनाव हुए, चाहे स्थानीय निकायों के हों, पंचायतों के हों, मेयर के हों या फिर उपचुनाव, सभी चुनावों में हमने लगातार विजय हासिल की। सभी 10 लोकसभा सीटें हमने जीती। तो ये मोदीजी की लोकप्रियता, अच्छी रणनीति और हमारी राज्य सरकार जो पांच साल ईमानदारी से चली, उसके कारण से संभव हुआ।

हरियाणा सरकार की ऐसी कौन सी प्रमुख उपलब्धियां हैं जिनके चलते पार्टी को पुनः जनसमर्थन प्राप्त हुआ?

अब हरियाणा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का प्रदेश नहीं रहा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि यह सरकार ईमानदार सरकार है। पारदर्शी सरकार है। इसने नौकरियों में पारदर्शिता रखी। पर्ची और खर्ची के बगैर नौकरियां दीं। सबसे बड़ा काम हमारी सरकार का यही था। बहुत काम हुए। गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा लेकिन प्रमुख रूप से देखें तो सरकार की ईमानदार छवि, हरियाणा एक - हरियाणवी एक, भेदभाव के बिना विकास, पारदर्शी तरीके से नौकरियां उपलब्ध कराने का काम, सही ट्रांसफर पॉलिसी; ये ऐसे काम हैं जिनके कारण से सरकार की एक छवि निखरकर आई।

हरियाणा किसान प्रधान राज्य है। किसानों के हित में सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं?

हरियाणा ने सबसे पहले जितना मुआवजा कहा, उतना दिया। केंद्र

सरकार ने मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ाया, हरियाणा ने दो गुना बढ़ा दिया। पहले 50 प्रतिशत फसल के नुकसान पर मुआवजा मिलता था, अब 33 प्रतिशत पर मिलने लगा। हरियाणा ने शुरू-शुरू में 2100 करोड़ का मुआवजा दिया। जबसे हरियाणा बना तबसे 2014 तक कुल मिलाकर 1200 करोड़ का मुआवजा दिया गया है और हमारी सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक 3600 करोड़ का करीब-करीब मुआवजा दिया गया है। पर्याप्त मुआवजा देना अर्थात् सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फिर किसानों को भावांतरण योजना से लाभान्वित करना, ये सरकार और किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात, एक-एक दाना खरीदना। दूसरे प्रदेश के किसान भी लेकर आ जाते हैं क्योंकि हरियाणा के किसानों का दाना-दाना खरीदा जाता है, तो ये खरीद पूरी करना बड़ी बात है। खरीद में केवल धान ही नहीं, केवल गेहूं ही नहीं, तो सूरजमुखी, बाजरा, सब प्रकार की फसलें हैं, इनकी खरीद की योजना बनाई जाती है। 92 प्रतिशत तक एमएसपी बढ़ाकर खरीदा है। दक्षिण हरियाणा का सूखेग्रस्त किसान भी बाजरे की खेती कर लाभप्रद रह सकें, इसकी योजना को क्रियान्वित किया। केंद्र में मोदीजी ने लागू की थी, उसको सही स्तर पर हरियाणा ने अपने यहां लागू किया है।

युवाओं के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा रहता है कि उन्हें रोजगार मिले। इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से किस तरह के प्रयास किए जा रहे है?

हरियाणा में युवाओं के हित में सरकार अनेक योजनाएं चला रही है और गंभीरता से प्रयास कर रही है। आज सबसे ज्यादा खुश युवा है क्योंकि खेलों में सबसे ज्यादा उन्नति, प्रगति, खिलाड़ियों को नौकरी, खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि, पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। दूसरा, युवाओं के लिए नौकरी, ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। युवा सबसे ज्यादा इस बात से खुश है। अभी 62 हजार नौकरियां दी थी और नौकरियां निकलने वाली हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल नौकरी से युवा को रोजगार नहीं दिया जा सकता, हमें रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर अधिक रोजगार सृजन करना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने करीब-करीब 16 लाख लोगों को मुद्रा लोन दिए हैं। उल्लेखनीय है कि एक आदमी अकेला अपना काम नहीं करता तो 2-3 लोगों को रोजगार देगा तो 30-40 लाख लोगों को रोजगार वही दे देगा, तो इस प्रकार से ये हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी प्राइवेट नौकरियां हैं, उनमें 75 प्रतिशत हरियाणा के लोगों को नौकरी मिलें, कम से कम क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियों में, इसकी चिंता सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा था कि राज्य में हम एनआरसी लागू करेंगे तो इसकी क्या जरूरत है यहां?

एनआरसी तो पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। हरियाणा में भी बंगलादेशी घुसपैठिए आकर रहते हैं। फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, गुड़गांव जैसे अनेक जगहों पर हैं, घुसपैठिए यहां क्यों रहे? यह देश से जुड़ा विषय है इसलिए मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि ये सारे प्रदेश में लागू होने चाहिए, यह ठीक है। हरियाणा देश का हिस्सा है।

केंद्र में भी भाजपा सरकार है। आपकी दृष्टि में इस सरकार की क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं?

केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को विश्व पटल पर सबसे ऊंचा रखा है, आजादी के बाद यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहूंगा क्योंकि मेरे साथ किस्से जुड़े हैं। मैं लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। मेरे साथ के सौ लोग बाहर होंगे। ये लोग पहले क्या कहते थे और आज कितने गर्व से रहते हैं, इससे पता लगता है कि भारत ने कितनी बड़ी प्रगति की है। सारी दुनिया में प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, तो लोग मोदी-मोदी के नारे से उनका स्वागत करते हैं, सारी दुनिया देखकर दंग रहती है। देश के प्रधानमंत्री का इतना मान-सम्मान होता है, बड़े से बड़ा राष्ट्राध्यक्ष पलक-पावड़े बिछाकर मोदी का स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खाने-पीने से बड़ी चीज सम्मान है। देश के सम्मान की बात आती है तो व्यक्तिगत सम्मान भी पीछे रह जाता है। मोदीजी ने सबसे बड़ा काम मेरी दृष्टि में अगर कोई किया है तो देश का सम्मान दुनिया की नजर में बहुत ऊंचा किया है।

देश की सुरक्षा के प्रति देश में जिस प्रकार की गंभीरता मोदीजी ने दिखाई, वह उल्लेखनीय है। चाहे वो पुलवामा के बाद बालाकोट की घटना हो या चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की घटना हो, दुनिया में अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है, जो दूसरे के देश में जाकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले सकता है। हमने ऐसा करके दिखाया। एक बार नहीं, दो-दो बार करके दिखाया। दुनिया भी भारत की शक्ति को मानने लगी है। प्रधानमंत्री मोदीजी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को समझने लगी है।

तीसरी बात, मैं जनकल्याण की कहूंगा। गरीब अपने दम पर खड़ा हो सके, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अंत्योदय लागू करना हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। अंत्योदय मतलब गरीब कल्याण, हम इसे साकार कर रहे हैं। 2022 तक सबके सिर पर छत हो, 2 करोड़ से ज्यादा घर मोदी जी ने बनाकर दिए है। 12 करोड़ की जनसंख्या इससे प्रभावित हुई। 8-9 करोड़ शौचालय बनवाकर दिए। कितने परिवारों को इसने प्रभावित किया। गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, गैस दी। फिर तमाम तरह की उनको सहूलियतें दीं। आयुष्मान भारत की योजना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 50 करोड़ प्रभावित हुए इससे। 5 लाख तक का बीमा। अभी तक करीब-करीब देश में 30-35 लाख लोगों ने इसका लाभ ले लिया है। तो ऐसी योजनाएं, जिससे देश का गरीब स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर देश की प्रगति में साथ दे सके, चलाई जा रही हैं। यह संवेदनशीलता दिखाता है कि नेतृत्व की दिशा क्या है। इसमें 100 फीसदी खरे उतरे हैं मोदीजी। उनके नेतृत्व में देश सही मायने में आगे बढ़ रहा है। अभी तो अपार संभावनाएं हैं, आगे ऐसे प्रयास होते रहेंगे। ■

सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह, केवडिया (गुजरात)

'हमें अपनी विविधता में एकता पर गर्व है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की समृद्ध विविधता और सदियों पुरानी जीवन शैली की सराहना करते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय एकता और एकजुटता बनाए रहने के संकल्प में सहायता की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी विविधता में एकता पर गर्व है। इससे हमें पहचान और सम्मान मिलता है। हम विविधता में एकता का उत्सव मनाते हैं। हमें अपनी विविधता में कोई अंतर्विरोध नहीं दिखता, बल्कि इसमें एकता का मजबूत सूत्र दिखता है।

उन्होंने कहा कि हम विविधता में एकता का उत्सव मनाते हैं, विविधता का पर्व वास्तव में हमारे दिलों में एकता के तार को स्पर्श करता है। जब हम अलग-अलग जीवन शैली और परंपरा का सम्मान करते हैं तो सौहार्द और भाईचारा बढ़ता है और इसलिए हमें अपनी विविधता का समारोह मनाना चाहिए और यह राष्ट्र निर्माण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में किसी ओर जगह नहीं मिलती। दक्षिण भारत से आए शंकराचार्य ने उत्तर में मंदिर की स्थापना की और बंगाल के स्वामी विवेकानंद ने दक्षिण के कन्याकुमारी में ज्ञान की प्राप्ति की।

उन्होंने कहा कि पटना में जन्मे गुरू गोविंद सिंह ने पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की और रामेश्वरम में जन्मे ए. पी. जे. अब्दुल कलाम देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में "वी द पीपुल" का जिक्र देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह संविधान की शुरुआत में केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भारत में जीवन की हजारों साल पुरानी संरचना का प्रदर्शन है। जब सरदार पटेल के सामने देश भर में 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करने की बड़ी चुनौती थी, तो यह वह चुंबकीय शक्ति थी जिसने उन्हें भारत से जुड़े रहने के लिए आकर्षित किया।

श्री मोदी ने कहा कि जो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते, वो हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सदियों की ललक के बाद भी कोई भी हमारे बीच से एकता की इस भावना को परास्त नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की शुभकामनाओं के साथ देश में कुछ सप्ताह पहले ऐसी अलगावादी शक्तियों को परास्त करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को सिर्फ अलगाववाद और आतंकवाद दिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से इस अनुच्छेद ने देश के लोगों के बीच फूट पैदा की है।

श्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने अलगागवादी विचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया और हमारे भाई और बहने जो इस छद्म दीवार के दूसरी ओर थे वो इससे भ्रम की स्थिति में थे।

प्रधानमंत्री ने कहा अब ये दीवार नष्ट हो चुकी है। पूरे देश भर में सिर्फ जम्मू और कश्मीर एक ऐसा स्थान था जहां अनुच्छेद 370 लागू था। पिछले तीन दशकों में 40 हजार से अधिक लोग आतंकवादी गतिविधियों के कारण मारे गए, माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, बहनों ने भाइयों को खोया और बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया।

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरदार पटेल ने कहा था कि यदि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा मेरे पास रहता तो इसका समाधान करने में इतना समय नहीं लगता।" मैं अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के इस निर्णय को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें समर्पित करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारा यह निर्णय जम्मू और कश्मीर को विकास के पथ पर सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए खंड विकास परिषद के चुनावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा "इसमें 98 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। मतदाता जो कि पंच और सरपंच थे, उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान किया और इसने एक बड़ा संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थायित्व का दौर शुरू होगा। व्यक्तिगत रुचि के चलते सरकार बनाने का खेल अब खत्म होगा और क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव की भावना भी दूर होगी। क्षेत्र में सहयोगी संघवाद की सच्ची भावना की शुरुआत होगी। नए राजमार्ग, नई रेलवे लाइन, नए स्कूल, नए कालेज, नए अस्पताल जम्मू और कश्मीर को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे।

सरदार पटेल के आदर्शों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा "देश में स्थायित्व के लिए उद्देश्य में एकता, प्रयास में एकता और लक्ष्य में एकता आवश्यक है और यह सरदार पटेल की विचारधारा है कि हमें अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रयोजन में समतावादी भाव रखने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम राष्ट्रीय एकता के इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, तब ही हम "एक भारत- श्रेष्ठ भारत" का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ■

भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर

सऊदी अरब के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत चौथा देश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब की एक दिन की आधिकारिक यात्रा की। तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी सहयोग के अहम मुद्दों पर तत्काल निर्णय के लिए एक संयुक्त सामरिक भागीदारी परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही, दोनों देशों ने तेल और गैस, रक्षा एवं नागर विमानन समेत अलग-अलग प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौतों पर 29 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए।

गौरतलब है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और यह भारत की कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 18 प्रतिशत और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस की 30 प्रतिशत आपूर्ति करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत संबंध और दृढ़ होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश असमानता को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जी-20 के अंतर्गत मिलकर कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तेल के स्थिर मूल्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में अहम भूमिका निभाने के लिए सऊदी अरब प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने कहा, "पड़ोस सर्वप्रथम" उनकी सरकार की विदेश नीति के लिए मार्गदर्शक है। सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध हमारे विस्तारित पड़ोस के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है।

भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में 29 अक्टूबर को वैश्विक वित्तीय सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफानरी, पाइपलाइन, गैस टर्मिनल समेत ऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 2024 तक 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

श्री मोदी ने विश्व भर से जुटे निवेशकों को भारतीय स्टार्टअप में उद्यम पूंजी निवेश के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, ''भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश है।"

श्री मोदी ने कहा, ''एशिया में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 700 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है। भारत में यह क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर से बढ़ेगा।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत में प्रशिक्षित श्रमबल की जरूरत को पूरा करने के लिये 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का विस्तार मानव संसाधन क्षेत्र में भी किया जाना चाहिये, इन्हें केवल माल-व्यापार तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिये। श्री मोदी ने कहा, ''भारत रिफानरी, पाइपलाइन, गैस टर्मिनल समेत ऊर्जा क्षेत्र का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 2024 तक 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा। भारत को अपनी तेजी बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।"

सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने की योजना डीबीटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये 20 अरब डॉलर की बचत की गई है।

मेरा लक्ष्य सबसे निर्धन व्यक्ति को सशक्त करना है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य सबसे निर्धन

शेष पेज न. 31 पर...

भारत-जर्मनी के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा समेत 17 क्षेत्रों में समझौता

सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए दोनों देश जारी रखेंगे आपसी सहयोग

जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने एक नवंबर को 17 समझौते और पांच संयुक्त संकल्प-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा, नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने पांचवें भारत-जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध, लोकतंत्र और कानून के शासन के मूलभूत विश्वास पर आधारित है। अंतर-सरकारी परामर्श की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अनूठी व्यवस्था ने भारत और जर्मनी के बीच नयी और आधुनिक प्रौद्योगिकी, ई-मोबिलिटी, फ्यूल

जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए अनुबंधों/समझौता ज्ञापनों सूची

- इसरो और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के बीच कार्मिक आदान-प्रदान की व्यवस्था लागू करना
- नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा
- अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों के नेटवर्क में सहयोग के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
- कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
- स्टार्ट-अप के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में आशय की घोषणा
- कृषि बाजार विकास के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग बनाने के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा
- व्यावसायिक रोगों तथा दिव्यांग बीमित व्यक्तियों/कामगारों के पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
- अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
- वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, स्थापित करने और विस्तार करने के बारे में समझौता ज्ञापन
- आयुर्वेद, योग और ध्यान में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारी की अवधि के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन
- कृषि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग पर निएनबर्ग शहर में जर्मन कृषि अकादमी डीईयूएलए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज के बीच समझौता ज्ञापन
- सतत विकास के लिए कौशल पर आर्थिक सहयोग और विकास के बारे में भारत सीमेंस लिमिटेड इंडिया, एमएसडीई और जर्मन मंत्रालय के बीच आशय की संयुक्त घोषणा
- उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदारी के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन
- नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रशियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और बर्लिनर श्लॉस में स्टेफ्टुंग हम्बोल्ट फोरम के बीच सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और ड्यूशेरफुबॉल-बुंद ई.वी. (डीएफबी) के बीच समझौता ज्ञापन
- इंडो-जर्मन प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के प्रमुख तत्वों पर आशय का विवरण।

सेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी, अंतरदेशीय जलमार्ग, समुद्र तट प्रबंधन, नदियों की साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर को नई दिल्ली में जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उद्घाटन वक्तव्य दिया। जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चांसलर डॉ. मर्केल ने भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता का समर्थन देने के लिए जर्मनी का कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए आपसी सहयोग जारी रखेंगे।

प्रधानमंत्री ने जर्मनी की चांसलर के साथ गांधी स्मृति का किया दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक नवंबर को नई दिल्ली में जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ गांधी स्मृति का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जर्मनी की चांसलर की अगवनी की। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मभूषण श्री राम सुतार ने बनाया है।

इस स्थल के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉ. मर्केल को बताया कि गांधी स्मृति वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के कुछ महीने गुजारे थे और 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या हुई थी।

दोनों विश्व नेताओं ने उसके बाद संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय में प्रतिष्ठित कलाकार श्री उपेन्द्र महारथी तथा शांतिनिकेतन के श्री नंद लाल बोस की छात्रा इंडो-हंगेरियन चित्रकार एलिजाबेथ ब्लूनर द्वारा बनाए रेखाचित्रों और पेंटिंग का अवलोकन किया। उन्होंने श्री बिराद राजाराम याज्ञनिक द्वारा तैयार डिजिटल वीथिका को भी देखा, जो अहिंसा और सत्याग्रह की विषयवस्तु पर बनी है।

इसके बाद दोनों नेताओं ने संग्रहालय में विविध डिजिटल अधिष्ठापनाओं को देखा, जिनमें महात्मा गांधी के बारे में अलबर्ट आइंस्टीन का कथन शामिल है। इसके अलावा 107 देशों में गाये जाने वाले 'वैष्णव जन तो' का गायन संबंधी इंटरऐक्टिव कियॉस्क भी देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने शहीद स्तंभ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। ■

पेज न. १९ का शेष...

व्यक्ति को सशक्त करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले ये सुनिश्चित कराना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमेशा इस बात पर विचार करते रहते हैं कि भारत, विश्व को बेहतर बनाने में कैसे योगदान कर सकता है। भारत में चल रहे हमारे कार्यक्रम विश्व भर में चल रहे ऐसे कार्यक्रमों को ओर मजबूती प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए विश्व से वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य के मुकाबले हमारा लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है। जब भारत इसमें सफल होगा तो संपूर्ण विश्व अधिक स्वस्थ बनेगा।

प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के शाह, क्राउन प्रिंस से रियाद में मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से रियाद में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद विश्व के सबसे अधिक सम्मानित नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ सहयोग को ओर अधिक सशक्त करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद से बातचीत की। बैठक के दौरान ऊर्जा संबंधी कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिससे भारत-सऊदी अरब मित्रता को ओर अधिक शक्ति दी जा सके। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारत-सऊदी अरब के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बना रहेगा।

प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के शाह से रियाद में मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम (एफआईआई) के दौरान जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह द्वितीय बिन एल-हुसैन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को ओर मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। इसमें जॉर्डन के शाह की 27 फरवरी 2018 से 1 मार्च, 2018 तक भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र और समझौते भी शामिल थे।

दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और अन्य क्षेत्रीय घटनाओं पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जॉर्डन के शाह के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया।

भारत और जॉर्डन के बीच प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक जुड़ाव, सांस्कृतिक संबंध और नागरिकों के बीच संपर्क कायम रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जॉर्डन दौरे और जॉर्डन के शाह के वर्ष 2018 हुए भारत दौरे ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति दी है, जो विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर पारस्परिक सम्मान और समन्वय से चिन्हित होता है। ■

'सशक्त आसियान से भारत को काफी लाभ मिलेगा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 से 4 नवंबर के दौरान थाईलैंड के बैंकाक की यात्रा की। यहां पर श्री मोदी ने 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की तीसरी शिखर बैठक में भाग लिया।

श्री मोदी ने 3 नवंबर को बैंकॉक में 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 16वें भारत–आसियान का हिस्सा बनने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए थाईलैंड को धन्यवाद दिया और अगले वर्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लेने के लिए वियतनाम के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत–प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केन्द्र है। एक सशक्त आसियान से भारत को काफी लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने भूतल, समुद्र, वायु एवं डिजिटल संपर्कता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भौतिक और डिजिटल संपर्कता में सुधार की दृष्टि से एक अरब डॉलर का भारतीय ऋण लाभदायक साबित होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के यादगार शिखर सम्मेलन और सिंगापुर अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के निर्णयों के लागू होने से भारत और आसियान एक–दूसरे के निकट आए। भारत और आसियान के लिए परस्पर लाभदायक क्षेत्रों में सहयोग एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत इच्छुक है। उन्होंने कृषि, अनुसंधान, अभियंत्रण, विज्ञान और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए दिलचस्पी दिखाई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा एवं नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने भारत–आसियान एफ. टी. ए की समीक्षा के बारे में हाल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया

म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 नवंबर को म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति और पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत द्वारा म्यांमार को साझेदार देश के रूप में दी जाने वाली प्राथमिकता पर बल दिया। इस दिशा में

उन्होंने म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया तक सड़क, बंदरगाह और अवसंरचना निर्माण के माध्यम से भारत के वास्तविक संपर्क में सुधार लाने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता पर महत्व दिया।

उन्होंने कहा कि भारत, म्यांमार की पुलिस, सेना और लोक सेवकों साथ-ही-साथ छात्रों और नागरिकों की क्षमता में विस्तार के प्रति ठोस सहायता देना जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि जनता के बीच आपसी संपर्क से उनकी साझेदारी का आधार व्यापक बनेगा।

उन्होंने दोनों देशों के बीच वायु संपर्क के विस्तार तथा म्यांमार में भारत के बढ़ते कारोबारी हितों का स्वागत किया। इन कारोबारी हितों में नवंबर, 2019 के आखिर में भारत सरकार द्वारा यांगुन में सीएलएमवी देशों (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) के व्यापारिक आयोजन की मेजबानी की योजना शामिल है।

प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकॉक में आसियान/ईएएस संबंधित बैठकों के दौरान 3 नवंबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक और बहुसंख्यक समाजों के रूप में भारत इंडोनेशिया के साथ प्रतिरक्षा, सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश तथा लोगों का लोगों के साथ परस्पर विनिमय के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह देखते हुए कि भारत और इंडोनेशिया करीबी समुद्री पड़ोसी हैं, दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर अपना साझा विजन अर्जित करने हेतु शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने चरमपंथ और आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की और इस खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर घनिष्ठतापूर्वक काम करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधानमंत्री थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 03 नवंबर को थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) प्रयात चान-ओ-चा से मुलाकात की।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और नोट किया कि सभी स्तरों पर नियमित उच्च स्तरीय बैठकों और विनिमयों ने संबंधों में सकारात्मक गति का सृजन किया है। प्रतिरक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए सहमत जताई। पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार में हुई 20% की वृद्धि का स्वागत करते हुए दोनों नेताओं ने व्यापार अधिकारियों पर व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का दायित्व सौंपा।

प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जिसमें वास्तविक और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते हवाई संपर्क और बैंकॉक और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू करने तथा थाईलैंड के रानोंग बंदरगाह एवं कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम के भारतीय बंदरगाहों के बीच सहयोग के लिए समझौतों को अंतिम रूप दिये जाने का स्वागत किया।

नेताओं ने पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान से संबंधित बैठकों में शामिल होने के लिए उन्हें दिए गए निमंत्रण के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्हें आसियान के अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व पर बधाई दी। उन्होंने इस संबंध को और मजबूत करने हेतु भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी के लिए देश समन्वयक के रूप में थाईलैंड के योगदान का सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया।

करदाताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए भारत ने उठाये कई कदम: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन नवंबर को कहा कि उनकी सरकार ने करदाताओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कर संग्रह के क्षेत्र में कई बड़े कर सुधार किए हैं। पिछले पांच साल में उनकी सरकार द्वारा किए गए वित्तीय सुधारों का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि भारत में कर आकलन के दौरान करदाताओं का उत्पीड़न रोकने के लिये ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें करदाता और कर अधिकारी को आमने-सामने आने की जरूरत नहीं है।

थाइलैंड में आदित्य बिड़ला समूह के परिचालन की स्वर्ण जयंती के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अनुकूल कर व्यवस्था वाला देश बन गया है, और इस प्रणाली में और सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से देश में आर्थिक दृष्टि से एकीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे और अनुकूल बनाने के लिए काम कर रही है।

श्री मोदी ने कहा, ''पिछले पांच साल के दौरान हमने मध्यम वर्ग से कर का बोझ काफी कम किया है। अब हम ऐसी कर व्यवस्था शुरू कर रहे हैं जिसमें करदाता और कर अधिकारी का आमना सामना नहीं होगा, जिससे करदाता के किसी तरह के उत्पीड़न की गुंजाइश समाप्त होगी।

श्री मोदी ने कहा, ''आज के भारत में मेहनत से काम करने वाले करदाता के योगदान को सराहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां हमने काफी काम किया है, वह है कराधान। मुझे खुशी है कि आज भारत में दुनिया की सबसे अनुकूल कर व्यवस्था है। हम इसमें और सुधार करने को प्रतिबद्ध हैं।" अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट कर में कटौती का भी जिक्र किया। ■

गुरुनानकदेव जी का प्रभाव भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित अपने मासिक संबोधन 'मन की बात' में 27 अक्टूबर को कहा कि 12 नवंबर, 2019; यह वो दिन है, जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरुनानकदेव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। गुरुनानक देव जी का प्रभाव भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व मे है। दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाई-बहन बसे हुए हैं जो गुरुनानकदेव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मैं वैंकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरुनानकदेव जी बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरुनानकदेव जी मानते थे कि निःस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई क़ीमत नहीं हो सकती। वे छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरुनानक देव जी ने अपना सन्देश दुनिया में दूर-दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। वे कई स्थानों पर गये और जहां भी गये, वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। गुरुनानक देव जी ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं की, जिन्हें 'उदासी' कहा जाता है। सद्भावना और समानता का सन्देश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम - हर दिशा में गये, हर जगह लोगों से, संतों और ऋषियों से मिले।

उन्होंने कहा कि माना जाता है कि असम के सुविख्यात सन्त शंकरदेव भी उनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने हरिद्वार की पवित्र भूमि की यात्रा की। काशी में एक पवित्र स्थल, 'गुरुबाग गुरुद्वारा' है– ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरुनानक देव जी वहां रुके थे। वे बौद्ध धर्म से जुड़ी 'राजगीर' और 'गया' जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए थे। दक्षिण में गुरुनानक देव जी श्रीलंका तक की यात्रा की। कर्नाटक में बिदर की यात्रा के दौरान गुरुनानक देव जी ने ही वहां पानी की समस्या का समाधान किया था।

श्री मोदी ने कहा कि बिदर में 'गुरुनानक जीरा साहब' नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है जो गुरुनानक देव जी की हमें याद भी दिलाता है, उन्हीं को ये समर्पित है। एक उदासी के दौरान गुरुनानक जी ने उत्तर में, कश्मीर और उसके आसपास के इलाके की भी यात्रा की। इसे सिख अनुयायियों और कश्मीर के बीच काफी मजबूत सम्बन्ध स्थापित हुआ।

उन्होंने कहा कि गुरुनानक देव जी तिब्बत भी गये, जहां के लोगों ने उन्हें 'गुरु' माना। वे उज्बेकिस्तान में भी पूजनीय हैं, जहां उन्होंने यात्रा की थी। अपनी एक उदासी के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। वे लाखों लोगों के दिलों में बसे, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही करीब 85 देशों के के राजदूत दिल्ली से अमृतसर गये थे। वहां उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किये और ये सब गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशपर्व के निमित्त हुआ था। वहां इन सारे राजदूतों ने स्वर्ण मंदिर के दर्शन तो किये ही, उन्हें सिख परम्परा और संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला। इसके बाद कई राजदूतों ने सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें साझा की। बड़े गौरवपूर्वक अच्छे अनुभवों को भी लिखा।

उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हमें उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की और अधिक प्रेरणा दें। एक बार फिर मैं शीश झुकाकर गुरुनानकदेव जी को नमन करता हूं। ■

बैंकाक (थाइलैंड) में पीआईओ व एनआरआई सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बैंकाक (थाइलैंड) में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में बिजनेस लीडर्स के साथ एक ग्रुप फोटो में जर्मन चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रियाद (सऊदी अरब) में सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बैठक करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 'ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट, 2019' को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत-पाकिस्तान करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करने के बाद सुलतानपुर लोधी (पंजाब) स्थित गुरुद्वारा बेर साहिब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पठानकोट (पंजाब) में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर सरदार बल्लभभाई पटेल जयंती (31 अक्टूबर) पर उन्हें श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20